भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

आपके बीच क्यों?

बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और
जनता की लूट के खिलाफ़ !
रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और भाईचारे के लिए !

सहयोग राशि: 10 रुपये

यदि जनबल पर विश्वास है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की दुर्दम शक्ति ने, फ़ासिज्म की काली घटाओं में, आशा के विद्युत का संचार किया है। वही अमोघ शक्ति हमारे भविष्य की भी गारण्टी है।

अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दे या समाप्त कर दे।

— शहीदेआज़म भगतसिंह

साथियो,

हम एक ऐसे दौर में आपसे मुख़ातिब हैं जब देश की जनता बढ़ती बेरोज़गारी, कमरतोड़ महँगाई, लोगों की पहुँच से दूर होती शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रही है। नौजवानों की एक बड़ी आबादी हताशा-निराशा का शिकार है। छात्रों-कर्मचारियों-मज़दूरों समेत आम जनता का हर हिस्सा मौजूदा भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का शिकार है। हमसे रोज़गार के अवसर, पेंशन-भत्तों से लेकर विभिन्न सुविधाएँ और श्रम क़ानूनों के रूप में हर तरह की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को छीना जा रहा है।

एक ओर महँगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ग़रीबी, भूख और शोषण ने आम मेहनतकश जनता की कमर तोड़ रखी है, वहीं उसे धर्म के उन्माद में बहाया जा रहा है ताकि उसे उसकी ज़िन्दगी के असल मुद्दों से बहकाया जा सके। जनता के बीच जनता के ही एक हिस्से को नकली दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि हम असली दुश्मन की पहचान ही न कर सकें। **अंग्रेज़ों की 'बाँटो और राज करो' की नीति को मौजूदा सरकार पूरी निष्ठा से लागू कर रही है।**

समूचा मीडिया इस काम को अंजाम देने में मौजूदा सरकार की भरपूर मदद कर

रहा है। यही कारण है कि तमाम मीडिया बहसों में रोज़गार, महँगाई, शिक्षा जैसे हमारे जीवन के असली सवाल ग़ायब हैं और बेशर्मी से मन्दिर-मस्जिद, हिन्दू-मुसलमान, जातिवाद, अन्धराष्ट्रवाद पर जूतमपैजार होती है ताकि ग़ैर-मुद्दों को मुद्दा बनाकर हमें भरमाया जा सके। **इसकी वजह यह है कि पूरा मीडिया खुद बड़े-बड़े धन्नासेठों के ही हाथ में है।**

आज़ादी के 75 सालों में जनता ने भाजपा से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, जदयू, आप जैसे तमाम दलों को मौक़ा देकर उनकी सच्चाई देख ली है। बड़े-बड़े धन्नासेठों, अमीरज़ादों, मालिकों, ठेकेदारों, बड़े दुकानदारों, बिल्डरों, धनी फार्मरों और तरह-तरह के धनपशुओं की विलासिता की मीनारें आम जनता के आँसुओं के समन्दर के बीचों-बीच और ऊँची होती जा रही हैं, न तो 'अच्छे दिन' आ रहे हैं और न 'ग़रीबी हट' रही है।

भाजपा की मोदी सरकार ने तो परजीवी धन्नासेठों और अमीरज़ादों की सेवा करने, जनता को लूटने, पूँजीपतियों की तिजोरियाँ भरने और भ्रष्टाचार में अब तक की सारी सरकारों के रिकार्ड तोड़ दिये हैं। यह सब धर्म और अन्धराष्ट्रवाद के उन्माद और नशे में जनता को बहाकर किया जा रहा है।

कांग्रेस की सरकारें अतीत में यही काम अन्य तरीकों से करती रही हैं। यह याद रखना चाहिए कि देश में निजीकरण की आँधी चलाकर जनता के पैसे से खड़े सार्वजनिक उपक्रमों को पहले योजनाबद्ध तरीके से बीमार बनाने और फिर कौड़ियों के दाम निजी पूँजीपतियों के हवाले करने की लहर कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू की थी। भाजपा सरकार तो उन्हीं नीतियों को और तेज़ गति से, अधिक दमनकारी तरीके से, धार्मिक उन्माद भड़काकर और तानाशाहाना तौर-तरीकों से लागू कर रही है और इसीलिए अम्बानी-अदानी, टाटा-बिड़ला आदि की चहेती बनी हुई है।

आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, टीडीपी आदि तमाम छोटे व क्षेत्रीय दल भी यह दिखला चुके हैं कि वे भी अपने-अपने तरीके से अपने-अपने राज्यों व क्षेत्रों में वहाँ के धन्नासेठों, धनी फार्मरों, ठेकेदारों, दलालों, बिचौलियों, बिल्डरों आदि की ही सेवा करते हैं और उन्हें आम जनता को लूटने की पूरी छूट और सहूलियत देने का ही काम करते हैं। ये दल भी धर्म और जाति के नाम पर अपने-अपने तरीके से

हमें बाँटकर ही अपनी गोटियाँ लाल करते हैं। **आप इस बात को अपने तजुरबे से जानते हैं।**

अपने आपको मेहनतकश जनता का प्रतिनिधि बताने वाले सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) जैसे दलों की स्थिति यह है कि कभी ये कांग्रेस की पूँछ में कंघी करते हैं तो कभी किसी अन्य चुनावबाज़ पार्टी की। ये मुख्यत: बड़े धन्नासेठों और अमीरज़ादों के बजाय मुख्यत: छोटे और मँझोले धन्नासेठों और अमीरज़ादों की सेवा करने में लगे हुए हैं और भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े पूँजीपतियों की पार्टियों से इनका मुख्य अन्तर बस यही है।

संक्षेप में, मौजूदा व्यवस्था में देश के करोड़ों-करोड़ मज़दूरों, छात्रों, युवाओं, कर्मचारियों, ग़रीब किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं है।

ऐसे दौर में हमें बरबस ही भगतसिंह के ये शब्द याद आ जाते हैं – **"जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी तरह की तब्दीली से वे हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए क्रान्तिकारी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है। लोगों को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जनता को ग़लत रास्ते पर ले जाने में सफल हो जाती हैं। इससे इंसान की प्रगति रुक जाती है और उसमें गतिरोध आ जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यह ज़रूरी है कि क्रान्ति की स्पिरिट ताज़ा की जाये, ताकि इंसानियत की रूप में हरकत हो।"**

इसी गतिरोध की स्थिति को तोड़ने और क्रान्ति की स्पिरिट को ताज़ा करने के लिए हम आपके बीच **"भगतसिंह जनअधिकार यात्रा"** लेकर आये हैं। हम आपको विश्वास दिलाने आये हैं कि अभी भी देश के समूचे आम मेहनतकश अवाम ने हर तरह के ज़ुल्म और अन्याय को अपनी क़िस्मत नहीं मान लिया है। हम यह बताने आये हैं कि हर तरह के जातिवाद, धार्मिक कट्टरपन्थ, अन्धराष्ट्रवादी उन्माद के घटाटोप के ख़िलाफ़ भगतसिंह और क्रान्तिकारियों के विचारों की मशाल लेकर बहुत से संवेदनशील और इंसाफ़पसन्द युवा अभी भी बदलाव की लड़ाई में जुटे हुए हैं। हम यह याद दिलाने आये हैं कि लम्बी से लम्बी रात के बाद सुबह आती है।

भगतसिंह जनअधिकार यात्रा का लक्ष्य है देश की जनता को अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में जागृत करना, सचेत करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए संगठित

होकर संघर्ष करना। **भगतसिंह जनअधिकार यात्रा का लक्ष्य है** जनता को इस सत्य से अवगत करना कि रोज़गार, सभी को समान व निशुल्क शिक्षा, सभी को समान व निशुल्क चिकित्सा, सभी को आवास, हर नागरिक को राजकीय बीमा और एक *सच्चे मायने में* सेक्युलर राज्य हमारे मूलभूत अधिकार हैं। अगर कोई सरकार हमें ये मूलभूत हक़ नहीं देती तो उसे सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई व्यवस्था हमें ये हक़ नहीं देती तो उस व्यवस्था के क़ायम रहने का कोई औचित्य नहीं है। **भगतसिंह जनअधिकार यात्रा का लक्ष्य** समाज में एक नयी क्रान्तिकारी जागृति लाना है। **भगतसिंह जनअधिकार यात्रा** का लक्ष्य यह सच्चाई उजागर करना है कि जनता अगर अपने *असली मसलों* को लेकर एकजुट हो जाये, संघर्ष करे तो वह अपने अधिकार हासिल कर सकती है, वह दुनिया बदल सकती है, इतिहास बना सकती है। **आज हमारे ये असली मसले क्या हैं?**

शिक्षा और रोज़गार! हमारा जन्मसिद्ध अधिकार!

आज देश की युवा आबादी बेरोज़गारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा करके सत्ता मे पहुँचने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थिति यह है कि देश की क़रीब **32 करोड़ आबादी** बेरोज़गारी का दंश झेल रही है। *सीएमआईई (सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकॉनमी)* के आँकड़ों के मुताबिक इस समय देश में बेरोज़गारी दर बढ़ते हुए कोविड के समय के स्तर पर पहुँच चुकी है। यही आँकड़े बता रहे हैं कि कोविड के दौर में बेरोज़गार हुए हर पाँच में से एक नौजवान को अभी तक रोज़गार नहीं मिल सका है। जो रोज़गारशुदा हैं, उन तक भी मन्दी की आँच पहुँच चुकी है और बहुत-सी प्रतिष्ठित कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करते हुए उनकी छँटनी शुरू कर दी है। यह छँटनी किस पैमाने पर हो रही है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि भारत में *ट्विटर* ने अपने 80 फ़ीसदी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाल ही *अमेज़ॉन* ने अपने 18,000 और *एचपी* ने अपने 6000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालने की बात कही है। जुलाई 2022 से लेकर अब तक *माइक्रोसॉफ़्ट* तीन बार और *नेटफ्लिक्स* दो बार छँटनी कर चुका है। हार्डड्राइव निर्माता कम्पनी *सीगेट* 3000 से ज़्यादा लोगों की छँटनी कर चुकी है।

नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न कम्पनियों में की गयी छँटनी को समझा जा सकता है।

कम्पनी	छँटनी (प्रतिशत में)
ट्विटर	50
क्रैकेन	30
कैमियो	25
रॉबिनहुड	23
ईटेल	20
स्नैपचैट	20
क्वाइनबेस	18
ओपेनडोर	18
मेटा	15
स्ट्राइप	14
शॉपीफ़ाई	10

यह तो सबसे ऊँची व अमीर कम्पनियों की हालत है। **पूरे देश में सभी कल-कारखानों, दफ्तरों-दुकानों, वर्कशॉपों आदि में यही हाल है।** नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता की मजबूरी का मज़ाक बनाने की इन्तहाँ यह है कि जब कोई रोज़गार न मिलने पर कोई रेहड़ी-खोमचा लगाता है, पकौडियाँ तलता है तो उसे रोज़गार का नाम दे दिया जाता है! **रोज़गार देने में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मोदी सरकार द्वारा ऐसी बेहूदा बातें की जाती हैं। सच्चाई यह है कि सारे बेरोज़गार मर नहीं जाते, आत्महत्या नहीं कर लेते। वे मजबूरी में कुछ हाथ-पाँव मारते हैं, पटरी दुकान लगाते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं, फेरी लगाते हैं और किसी तरह भुखमरी रेखा पर जीते हैं। और सरकार बेशर्मी से कहती है कि यह रोज़गार ही तो है! यह रोज़गार नहीं है, हमारी मजबूरी है, जिसका मोदी सरकार मख़ौल बना रही है।**

सरकारी भोंपू बन चुका मीडिया बड़ी बेशर्मी से विकास और तरक्की के दावों को दुहरा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरक्की केवल बेरोज़गारों की संख्या में हो रही है, यह विकास केवल आम जनता की तबाही-बदहाली में हो रहा है। **कोई तो वजह होगी कि मोदी सरकार अब कभी 'अच्छे दिनों' का ज़िक्र तक नहीं करती!**

मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 सालों के दौरान सरकारी सेक्टर में रोज़गार के बचे-खुचे

अवसरों को भी समाप्त कर दिया है। रेलवे, बैंक, बिजली, सिंचाई समेत कोई ऐसा विभाग नहीं है जो आज उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों का दंश न झेल रहा हो। स्थिति यह है कि देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले विभाग रेलवे में पिछले सात सालों में डेढ़ लाख से ज़्यादा पदों को समाप्त किया जा चुका है, और बचे हुए स्वीकृत पदों में से भी तीन लाख से अधिक पद खाली हैं। यही हालत अन्य विभागों की भी है। जुलाई 2022 में केन्द्रीय कार्मिक राज्य मन्त्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के आवेदन किये थे, जिसमें से केवल 7.22 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पायी है। इतना ही नहीं, सेना में 'अग्निवीर' के नाम पर ठेके पर सैनिक भर्ती करने की योजना के बाद अब यही प्रयोग सभी बैंकों सहित अन्य विभागों पर भी करने पर काम चल रहा है। याद रहे कि देशभक्ति और "राष्ट्रवाद" का ढोल बजाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा सरकार ठेके पर सैनिक भर्ती कर मज़दूरों-किसानों के बेटे-बेटियों के हक पर हाथ मार रही है। कारगिल युद्ध में मारे गये सैनिकों के लिए ताबूतों की ख़रीद में हुए घोटाले से लेकर 'अग्निवीर' के तहत पर ठेके पर सैनिक भर्ती तक नरेन्द्र मोदी और भाजपा की देशभक्ति और "राष्ट्रवाद" की सच्चाई जनता के सामने है। जो इतिहास से वाकिफ़ हैं, वे तो पहले से ही जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देशप्रेम से कोई लेना-देना नहीं था। **जो अंग्रेज़ों से मुखबिरी कर रहे थे, माफ़ीनामे लिख रहे थे और शहीदे-आज़म भगतसिंह की शहादत को बेकार बता रहे थे, और धर्म के नाम पर जनता की एकता को तोड़ने का काम कर रहे थे, उनकी "देशभक्ति" और "राष्ट्रवाद" की लफ्फाज़ी पर क्या आज भरोसा किया जा सकता है?**

नीचे दी गयी तालिका से विभिन्न सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या और उनके लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है!

विभाग	पद	आवेदन
रेलवे	90,000	2,80,00,000
महाराष्ट्र पुलिस कॉन्स्टेबल	1137	2,00,000
राजस्थान वि. स. सचिवालय	18	18,000

विभाग	पद	आवेदन
जिला न्यायालय, देवास (चतुर्थ श्रेणी)	34	8,000
पश्चिम बंगाल (ग्रुप डी)	6000	25,00,000

भीख माँगने और पकौड़ा तलने को भी रोज़गार बताने वाली मोदी सरकार के इस "रामराज्य'' में असल में रोज़गार के असली अवसर किस तरह से घटे हैं, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2012 से 2022 तक हर साल भर्तियाँ करने वाले विभागों में भर्तियों की संख्या बहुत तेज़ी से घटी हैं। जो भर्तियाँ हुई भी हैं, उनमें भी ज़्यादातर भ्रष्टाचार, पर्चा लीक, धाँधली की भेंट चढ़ चुकी है।

देश में जो आबादी रोज़गारशुदा है भी, उनमें से बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। इस आबादी के लिए न कोई श्रम क़ानून हैं और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा। *पीरियॉडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे ऑफ़ इण्डिया, 2021* के अनुसार देश में लगभग **दस करोड़ दिहाड़ी मज़दूर** और लगभग **पाँच करोड़ वेतनभोगी मज़दूर** बिना किसी लिखित अनुबन्ध के कार्य कर रहे हैं, यानी ठेके पर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर नियमित प्रकृति के कामों को नियमित मज़दूरों की जगह आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। 2004 के बाद से आउटसोर्स मज़दूरों की संख्या में 40 फ़ीसदी की वृद्धि हो चुकी है। **मोदी सरकार ने ठेका प्रथा को बढ़ावा देने में कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियों की सरकारों के रिकार्ड तोड़ दिये हैं।**

बेरोज़गार आबादी को स्वरोज़गार का झाँसा देने और *स्टार्टअप* तथा *मेक इन इण्डिया* के ज़ुमले की सच्चाई यह है कि **भारत में 95 प्रतिशत स्टार्टअप एक साल भी नहीं टिक पाते। जो बचे हुए स्टार्टअप हैं भी, उनमें से भी 85 प्रतिशत की मासिक आय दस हज़ार रुपये से कम है।**

वास्तव में देश में रोज़गार का यह संकट असमाधेय नहीं है। यह कोई भूकम्प तो है नहीं जिस पर मनुष्यों का नियन्त्रण न हो! चन्द मालिकों, धनी व्यापारियों, ठेकेदारों, धनी फार्मरों, आदि के निजी मुनाफ़े पर टिके असमान विकास के मॉडल की वजह से आज देश की एक बड़ी आबादी की ज़िन्दगी अँधेरे में धकेल दी गयी है। अगर पूरे देश स्तर पर गाँवों में अस्पताल, स्कूल, परिवहन आदि बुनियादी ज़रूरतों पर ही काम

किया जाये तो न केवल लोगों की सुविधाएँ बढ़ेंगी बल्कि इस प्रक्रिया में करोड़ों नौकरियाँ भी पैदा होंगी। *बहुत से सोचने-समझने वाले लोगों को भी लगता है कि आख़िर इसके लिए संसाधन कहाँ से आयेंगे। लेकिन अगर पैसों और संसाधनों की बात की जाये तो हमारे विविधतापूर्ण देश में न तो पैसों की कमी है और न ही संसाधनों की।* पिछले दस सालों में ही देश में 2.10 लाख करोड़ रुपये देश के पूँजीपति घरानों को बेलआउट पैकेज और करों में छूट के रूप में दिये जा चुके हैं। अगर पूँजीपति वर्ग और नेताओं-मन्त्रियों-नौकरशाहों की फ़िजूलखर्ची और असीमित सुविधाओं पर लगाम लगायी जाये तो देश में पैसों और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने वाली है।

इसी तरह अगर शिक्षा की बात की जाये तो चाहे बात प्राथमिक शिक्षा की हो या उच्च शिक्षा की, दोनों में ही आज हम तबाही के कगार पर खड़े हैं।

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत एक आँकड़े के अनुसार **देश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 9,07,583 पद खाली हैं।** नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों मे भी स्थिति यही है। केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में भी छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों के स्वीकृत पद पहले ही कम थे। इन स्वीकृत पदों में भी लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। **भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही हैं, जबकि पर्याप्त संख्या में सक्षम बेरोज़गार शिक्षक डिग्रियाँ लिए सड़कों पर घूम रहे हैं?** शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तन्त्र को ध्वस्त कर दिया गया है। इस तबाही-बर्बादी की क़ीमत पर फल-फूल रहे प्राइवेट स्कूल असल में शॉपिंग मॉल हैं, जहाँ से आप अपनी औकात के अनुसार सस्ती या मँहगी शिक्षा ख़रीद सकते हैं।

उच्च शिक्षा की बात करें तो देश भर के केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के **दो-तिहाई पद खाली** पड़े हैं। इन सरकारी विश्वविद्यालयों में पिछले लम्बे समय से 'सेल्फ़ फ़ायनेंस कोर्सेज़' को बढ़ावा देने के नाम पर इन्हें निजीकरण की दिशा में ढकेला जा रहा है। ज़्यादातर कक्षाओं को अतिथि या तदर्थ शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है और परमानेण्ट नियुक्तियाँ लगातार घटती जा रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख़्वाब अब मुट्ठी भर अमीरज़ादों के ही बस की बात रह गयी है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में तो स्थिति यह है कि जिन्दल, अशोका जैसे प्राइवेट विश्वविद्यालय बीए करने के लिए ही हर साल लाखों रुपये वसूलते हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी किसी तरह से हाईस्कूल-इण्टर पास करके या तो कहीं से आईटीआई-

पॉलिटेक्निक जैसे डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेती है या किसी प्राइवेट कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेती है और दिल्ली, मुम्बई, पंजाब, हरियाणा के औद्योगिक इलाक़ों में जाकर हड्डियाँ गलाती है।

मोदी सरकार द्वारा लायी गयी **नयी शिक्षा नीति** शिक्षा के निजीकरण-साम्प्रदायिकीकरण की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ाने वाली है। यह नयी शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को कम करने और प्राइवेट कम्पनियों के लिए शिक्षा को बिकाऊ माल बना देने के दरवाज़े खोल रही है। छठी कक्षा से ही छात्रों को काम-धन्धा सिखाकर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक व स्ववित्तपोषित कोर्स को बढ़ावा देकर यह शिक्षा नीति पूँजीपतियों के लिए सस्ते श्रमिकों की फौज़ खड़ी करेगी और जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, वे "पकौड़े तलेंगे"। पहले भी स्थिति यह थी कि छात्रों-युवाओं की एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा से पहले ही सरकार की नीतियों का शिकार होकर शिक्षा से बाहर खदेड़ दी जाती थी। आँकड़ों के मुताबिक केवल 12% छात्र ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पाते हैं। उनमें भी दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की बात करें तो उनकी संख्या और भी कम है। इस नयी शिक्षा नीति के अमल में आने के बाद ये हालात और भी भयावह होंगे। इसके लागू होने के दो साल के भीतर ही स्थिति यह हो गयी है कि सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को अपने खर्च का एक हिस्सा ख़ुद जुटाने को कहा गया है। नतीजतन, देश भर के विश्वविद्यालयों में फ़ीस बढ़ना शुरू हो चुकी है। पिछले साल ही दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बीएचयू, एमडीयू आदि जगहों पर फ़ीस वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे यह नीति अमल में आयेगी, आम छात्रों और शिक्षा के बीच खड़ी पैसे की दीवार और ऊँची होती जायेगी।

मोदी सरकार = महँगाई की मार!

मोदी सरकार के नौ सालों में जनता ने कमरतोड़ महँगाई का सामना किया है। बढ़ती क़ीमतों ने देश की मेहनतकश आबादी का जीना दूभर कर दिया है। मोदी सरकार के मन्त्रियों और टीवी चैनलों द्वारा बढ़ती महँगाई पर बेशर्मी भरे बयान देकर आम जनता की दुःख-तकलीफ़ों का मज़ाक बनाना भला कोई कैसे भूल सकता है। "बहुत हुई महँगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार" का नारा देकर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार की वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्याज की बढ़ती क़ीमतों पर बात करने पर बेशर्मी से ज़वाब दे दिया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इसी

तरह गोदी मीडिया जनता की परेशानियों पर मजाक बनाते हुए "पाकिस्तान में महँगाई" पर कार्यक्रम आयोजित करता है। ज़ाहिर है कि धन्नासेठों की चाकरी करने वाले इन नेताओं-मन्त्रियों को महँगाई, बेरोज़गारी की मार झेल रही जनता की दुःख-तकलीफ़ कभी महसूस नहीं हो सकती।

वस्तु	2014	2022
गैस सिलिण्डर	410	1050
पेट्रोल	70	100
डीज़ल	55	90
सरसों का तेल	90	200
दूध	35	60

आज डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस, किराये-भाड़े से लेकर आटे, सब्जियों समेत हर चीज़ की क़ीमत में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो चुकी है। देश की एक बहुत बड़ी मेहनतकश आबादी किन हालात में जी रही है, इसका अन्दाज़ा *ऑक्सफैम* की हालिया रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें बताया गया है कि देश की ऊपर की 1 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल सम्पत्ति का 40 प्रतिशत है, जबकि नीचे की 50 प्रतिशत आबादी के पास मात्र 3 प्रतिशत है। देश की लगभग तीन-चौथाई आबादी 30 से 40 रुपये रोज़ाना पर गुजर बसर करती है। *राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो* द्वारा 2012 में किये गये आख़िरी सर्वे में बताया गया था कि 1979 की तुलना में 2012 में औसतन हर ग्रामीण को 550 कैलोरी ऊर्जा, 13 ग्राम प्रोटीन, 5 मिग्रा आयरन, 250 मिग्रा कैल्सियम और 500 मिग्रा विटामिन ए प्रतिदिन कम मिल रहा था। अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि क़ीमतों के बढ़ने के बाद पिछले 10 सालों में ये आँकड़े और भी अधिक भयावह हुए हैं। अक्टूबर 2022 की *वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इण्डेक्स)* की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भुखमरी के मामले में भारत दुनिया के 121 देशों में 107वें स्थान पर है और एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से ग़रीब देशों से भी इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। वास्तव में, मोदी सरकार के "विकास" के सारे कीर्तिमान इसी मेहनतकश आबादी के विनाश की क़ीमत पर बनाये जा रहे हैं।

महँगाई बढ़ने का कारण है व्यापक मेहनतकश जनता की औसत आय में आने वाली भारी कमी, पूँजीपति वर्ग को भारी छूटें और रियायतें, जमाखोरी-सट्टेबाज़ी, भारी अप्रत्यक्ष कर और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की अराजकता। वैसे तो अधिकांश वस्तुएँ व सेवाएँ अब पहले से कम श्रम के व्यय में पैदा हो रही हैं क्योंकि श्रम की उत्पादकता पहले से कहीं ज़्यादा है। इस लिहाज़ से इनका *वास्तविक मूल्य* पहले से कम हो गया है। लेकिन चूँकि व्यापक जनता की औसत आय को पूँजीपति वर्ग ने मुद्रास्फीति व अन्य तरीकों के ज़रिये और भी ज़्यादा तेज़ी से घटाया है, तमाम व्यापारियों, आढ़तियों, बिचौलियों ने हर संकट पर ज़रूरी मालों की जमाखोरी और सट्टेबाज़ी की है, अप्रत्यक्ष करों का बोझ लगातार बढ़ाया गया है और मुनाफ़ा-केन्द्रित अराजक व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकता के अनुसार सुनियोजित उत्पादन नहीं किया जाता, इसलिए व्यापक मेहनतकश व आम जनता को रिकार्डतोड़ महँगाई का सामना करना पड़ रहा है। **आप देख सकते हैं कि महँगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं जिस पर नियन्त्रण सम्भव नहीं है, बल्कि यह मौजूदा मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था की नैसर्गिक पैदावार है।**

मोदी सरकार के राज में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त

सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन लाने, भ्रष्टाचार ख़त्म करने, काला धन वापस लाने जैसी बातें करने वाली भाजपा ने चुनाव बीतने के बाद ही इन मुद्दों को बेशर्मी से चुनावी जुमला घोषित कर दिया था। भ्रष्टाचार और काला धन ख़त्म करने के नाम पर नोटबन्दी से लेकर जीएसटी तक जो भी क़दम भाजपा सरकार ने उठाये, उनसे देश के धनपशुओं को ही फ़ायदा हुआ और वास्तव में आम लोगों के दुर्दिन और लम्बे हो गये। **हाल ही में हिण्डेनबर्ग खुलासे के बाद भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के ज़रिये गौतम अडानी द्वारा अकूत सम्पत्ति इकट्ठा किये जाने से भाजपा सरकार का चाल-चेहरा-चरित्र एक बार फिर से उजागर हो गया।** साथ ही, इनकी "देशभक्ति" और "राष्ट्रवाद" की भी पोलपट्टी खुल गयी। अमेरिकी 'एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर' संस्था हिण्डेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों और आँकड़ों सहित खुलासा किया कि अडानी समूह ने बहुत कम समय में पूँजी का जो साम्राज्य खड़ा किया है, उसके पीछे दशकों से स्टॉक क़ीमतों और बही-खातों की हेराफेरी, विदेशी 'टैक्स हैवेन' में अपने परिजनों द्वारा संचालित फ़र्ज़ी शेल कम्पनियों द्वारा अपने ही पैसे को अपनी ही कम्पनी में फ़िर से

निवेश करके उसके शेयर की क़ीमतों को बढ़ाने और इन ऊँची शेयर क़ीमतों को दिखाकर देश और दुनिया की तमाम वित्तीय संस्थओं से भारी-भरकम क़र्ज़ लेने की तिकड़म काम कर रही है। **अडानी के इस सम्पत्ति के पहाड़ को खड़ा करने में एलआईसी जैसी सार्वजनिक कम्पनियों तथा एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में जमा आम जनता के पैसों को भी झोंका गया है, जो तमाम सरकारी दावों के बावजूद डूब सकता है। ज़ाहिर है भ्रष्टाचार का यह पूरा पहाड़ बिना मोदी सरकार के सहयोग के खड़ा नहीं हो सकता था। मोदी जी यूँ ही अदानी के प्राईवेट हवाई जहाज़ों में तो कभी अदानी मोदी जी के जहाज़ में यात्रा थोड़े ही करते हैं!**

यह अनायास नहीं था कि हिण्डेनबर्ग खुलासे के बाद अडानी ने अपना बचाव करते हुए "राष्ट्रवाद'' का मुखौटा पहन लिया, तथा इसे देश और "राष्ट्र'' पर हमला बताने लगा। मोदी सरकार के लिए यह लाजिमी है क्योंकि उसके लिए तो देश का अर्थ अदानी, अम्बानी, टाटा-बिड़ला ही हैं! जब भी यह "देश के विकास" या "राष्ट्र के विकास" की बात करें, तो आप उसे "अदानी-अम्बानी-टाटा-बिड़ला का विकास" ही सुनें क्योंकि उनका यही अर्थ है। लेकिन हम जानते हैं कि **देश कोई कागज़ पर बना नक्शा नहीं है, बल्कि वह उसमें रहने वाले मेहनतकशों से बनता है, जो देश की समूची सम्पदा पैदा करते हैं।**

भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में **राफ़ेल ख़रीद** के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें 2012 से दसाल्ट एविएशन के साथ तय समझौते से तीन गुना अधिक क़ीमत देकर राफ़ेल विमान ख़रीदे गये और इस ख़रीद में सरकारी कम्पनी एचएएल की जगह अनिल अम्बानी की कम्पनी को ख़रीद में पार्टनर बनाया गया। इस भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते ही सरकार ने फ़िर "देश की सुरक्षा" का तर्क दिया। पूँजीपतियों और उनकी प्रतिनिधि सरकारों के लिए देश अथवा "राष्ट्र'' का मतलब देश में रहने वाले पूँजीपति ही होते हैं, जो देश की जनता के श्रम को निचोड़कर और देश की प्राकृतिक सम्पदा और संसाधनों का दोहन करके "राष्ट्र का विकास" करते हैं।

इसी तरह कोविड महामारी के समय जब देश की आम मेहनतकश जनता एक भयंकर त्रासदी झेल रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था की सारी कलई खुल चुकी थी, बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर थी तो उसी समय प्रधानमन्त्री मोदी ने 'आपदा को अवसर में बदलने' का नारा दिया और **पीएमकेयर्स फण्ड** की घोषणा की। इस फ़ण्ड के लिए न केवल बड़े पैमाने पर लोगों से दान करने की अपील की गयी, बल्कि राजस्व विभाग

ने अपने अधीन सभी कर्मचारियों को एक दिन का वेतन काटकर इस फ़ण्ड में जमा करने की बात कही। बाद में सरकार ने न्यायालय को बताया कि *पीएमकेयर्स कोई सरकारी संस्था नहीं है बल्कि एक प्राइवेट ट्रस्ट* है जिसके कामकाज पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है! **यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है?**

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार से लेकर तमाम राज्यों और केन्द्र की भर्ती परीक्षाओं ने भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों में नये रिकॉर्ड क़ायम किये हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं रही, जिसमें पर्चा लीक होने से लेकर धाँधली और भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं को सालों-साल कोर्ट का चक्कर न काटना पड़ा हो। इन घोटालों की सूची बनायें तो सैकड़ों पन्ने भर जायेंगे पर सूची ख़त्म नहीं होगी। भाजपा और तमाम राज्यों की पूँजीवादी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके पहले भी बंगारू लक्ष्मण द्वारा घूस लिये जाने, कारगिल ताबूत घोटाला, मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला बार-बार शुचिता-संस्कृति की दुहाई देने वाली भाजपा और संघ परिवार की असलियत दिखला चुके हैं। **ये घोटाले भाजपा सरकार का चाल-चेहरा-चरित्र उजागर करने के लिए काफ़ी हैं।**

जाति-धर्म के झगड़े छोड़ो! सही लड़ाई से नाता जोड़ो!

वैसे तो देश की आज़ादी के बाद से ही सभी चुनावबाज़ पार्टियों ने नकली सेक्युलरिज्म और जातिगत-धार्मिक समीकरणों के दम पर जनता को बाँटने-लड़ाने और अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम किया है, लेकिन फ़ासीवादी भाजपा के सत्ता में आने के बाद से हर तरह की तार्किकता, जनवाद और वैज्ञानिक चिन्तन को दफ़ना कर जनता के उन हिस्सों को जातिगत-धार्मिक-अन्धराष्ट्रवादी उन्मादियों की भीड़ में तब्दील करने की मुहिम चलायी जा रही है, जो सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता व असुरक्षा का शिकार हैं, न पूरी तरह आबाद हैं, न पूरी तरह बरबाद हैं, यानी मध्य, निम्न-मध्यवर्ग व अर्द्धमज़दूर आबादी। स्थिति यह हो गयी है कि दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक या स्त्री होना ही किसी अपराध जैसा हो गया है, जिन्हें एक नकली दुश्मन बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है ताकि असली दुश्मन नज़र से छिपा रहे। देश में हर घण्टे महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के 49 मामले दर्ज़ हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 2020 में बलात्कार के कुल 28,046 मामले दर्ज़ हुए थे, जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 31,677 पहुँच गयी।

एक तरफ़ शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार के अवसरों को समाप्त करके आम जनता के हितों पर चौतरफ़ा हमले किये जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ इन हमलों के ख़िलाफ़ एकजुट होने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों की ही तरह 'फूट डालो राज करो' की नीति अपनायी जा रही है।

एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट बताती है कि देश में हर घण्टे दलितों के ख़िलाफ़ अपराध के छः मामले दर्ज़ होते हैं। इनमें भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश अव्वल हैं जहाँ जातिगत अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। देश में जब "अमृतकाल'' की घोषणा की जा रही थी, उसी समय राजस्थान के जालौर में कक्षा तीन में पढ़ने वाले एक दलित छात्र इन्द्र मेघवाल की पानी पीने का मटका छू लेने के कारण पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी। इसी "अमृतकाल'' में आईआईटी मुम्बई में एक दलित छात्र ने जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले भी रोहित वेमुला से लेकर पायल तडवी तक सांस्थानिक हत्याओं का की एक पूरी श्रृंखला है, जिसे फ़ासीवादी भाजपा द्वारा पोषित जातिगत दम्भ की मानसिकता की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया है। गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई से

"...लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की ज़रूरत है। ग़रीब मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूँजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकण्डों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी ग़रीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताक़त अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी ज़ंजीरें कट जाएँगी और तुम्हें आर्थिक स्वतन्त्रता मिलेगी।"

- भगतसिंह (साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज)

लेकर इलाहाबाद में दलित परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराध इस व्यवस्था में आम हो चुके हैं। अस्मितावादी राजनीति के झण्डाबरदार ऐसी हर घटना के बाद अपनी अस्मितावादी राजनीति का शोर मचाते हैं और जाति-उन्मूलन की जगह जातिगत पहचान को मजबूत बनाने और समाज में जातिगत विभाजन को और अधिक सख़्त बनाने की राजनीति करते हुए ये अन्ततः भाजपा और संघ परिवार की फ़ासीवादी राजनीति को ही मजबूत करते हैं।

संघ परिवार और भाजपा ने पूरे देश में जो 'हिन्दू-मुस्लिम का नफ़रती खेल' शुरू किया है, उसका नतीज़ा यह हुआ है कि आज पूरे समाज में धार्मिक कट्टरपन्थ और उन्माद का माहौल बन चुका है। भाजपा सरकार द्वारा इस उन्माद के माहौल को बनाये रखने के लिए एनआरसी-सीएए जैसी साज़िश से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा के मामलों और 'लव ज़िहाद', हिज़ाब, गोरक्षा, आदि के मुद्दों को हवा दी जाती रही है। भाजपा के सत्ता में आने के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएँ तेज़ी से बढ़ी हैं। 2022 में लोकसभा में आँकड़ों की बाबत सवाल पूछने पर सरकार ने कहा कि सरकार और उसकी संस्थाएँ मॉब लिंचिंग के आँकड़ों को एकत्र ही नहीं करती हैं।

इतना ही नहीं, बड़े साम्प्रदायिक दंगों के अलावा पूरे देश भर में नफ़रती मुद्दों को भड़काकर स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा करने और दंगे कराने की एक परिपाटी चल रही है। *एनसीआरबी* के आँकड़ों के मुताबिक़ भारत में 2014 से 2020 के बीच साम्प्रदायिक दंगों की 5000 से अधिक घटनाएँ दर्ज़ की गयीं। इसका नतीज़ा यह हुआ है कि पूरे देश के स्तर पर हिन्दू-मुस्लिम आबादी के बीच में एक भयंकर दुराव पैदा हो गया है। भाजपा और संघ परिवार की इस धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीति का सीधा लाभ पीएफ़आई व ओवैसी जैसों की धार्मिक कट्टरपन्थ की राजनीति करने वाली पार्टियों को मिल रहा है। **वास्तव में एक कट्टरपन्थ, दूसरे कट्टरपन्थ को उभारकर और उसके पूरक के रूप में ही अपने-आप को बरक़रार रख सकता है।**

ऐसे में हम आपसे पूछना चाहेंगे: हर दंगे का फ़ायदा अन्त में किसे मिलता है? क्या दंगों में कभी किसी नेता-मन्त्री, पूँजीपति, नौकरशाह या अधिकारी का घर जलता है या उनके बच्चे मरते हैं? ज़रा पता करिये कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं के बेटे-बेटियाँ किन विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं? ज़रा सोचिये कि हमारे बेटे-बेटियों के हाथों में त्रिशूल और तलवार थमाकर अपने ही ग़रीब मेहनतकश भाइयों पर हमला करने को कहने वाले

लोगों के बच्चे किन ऐशो-आराम में जीते हैं?

साथियो, अब समय आ गया है कि हम धर्म के नाम पर मूर्ख बनना बन्द करें और समझ लें कि मेहनत करने वालों की एक जमात है और दूसरों की मेहनत पर मलाई चाँपने वालों की दूसरी जमात, वरना आने वाला समय हमारे लिए और भयंकर होगा। इसके अलावा, किसी भी बँटवारे का हमारे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी धर्म मानना या कोई भी धर्म न मानना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है। इसे हमारे सार्वजनिक जीवन में लाने से ही सारा झगड़ा, दंगे-फ़साद पैदा होते हैं, जिनका फ़ायदा हमेशा अमीरों को मिलता है और ग़रीब केवल उसमें अपनी जान-माल से हाथ धोते हैं, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों या कोई और। आप स्वयं अपने आपसे पूछें, आपको पता चल जायेगा कि यही सच है।

आज भारत समेत पूरी दुनिया का पूँजीपति वर्ग एक भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है: पूँजीपति वर्ग के मुनाफ़े की गिरती हुई औसत दर का संकट। पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटियों के रूप में काम करने वाली सरकारें उनके इसी मुनाफ़े की दर को बढ़ाने के लिए जनता की तमाम सुविधाओं में कटौती कर रही हैं। शिक्षा-चिकित्सा जैसी ज़रूरी चीज़ों से हाथ पीछे खींचकर उसे बाज़ार के हवाले कर देना, जनता की ख़ून-पसीने की कमाई से खड़े किये गये पब्लिक सेक्टर को पूँजीपतियों की झोली में डाल देना, सभी श्रम क़ानूनों और पर्यावरण सुरक्षा के क़ानूनों को समाप्त करके धन्नासेठों को मेहनत और कुदरत की लूट की और अधिक छूट देना, कर्मचारियों के पेंशन, भत्ते आदि को समाप्त कर जनता के ख़ून-पसीने की कमाई से बेलआउट पैकेज देना वास्तव में बढ़ते हुए संकट का ही परिणाम है।

इसकी वजह से पैदा होने वाले असन्तोष को रोकने के लिए ही जातिगत-धार्मिक-अन्धराष्ट्रवादी उन्माद का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि लोग अपने असली सवालों पर एकजुट न हो सकें। इसके पहले भी कांग्रेस से लेकर अन्य पार्टियों की सरकारों ने पूँजीपति वर्ग की ही सेवा की है, लेकिन आज बढ़ते हुए संकट के दौर में पूँजीपति वर्ग की सेवा करने और जनता के असन्तोष को भटकाने-भरमाने का काम जिस कुशलता के साथ फ़ासीवादी भाजपा और संघ परिवार कर सकता है, वह अन्य कोई पार्टी नहीं कर सकती। यही वजह है कि 'सॉफ्ट हिन्दुत्व' की

राजनीति से लेकर जातिगत समीकरणों और 'सोशल इंजीनियरिंग' की राजनीति करने वाले सभी दलों को छोड़कर पूँजीपति वर्ग ने भाजपा और संघ परिवार के लिए अपने खजाने को खोल दिया है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भाजपा को 614 करोड़ 53 लाख रुपये का, जबकि कांग्रेस को 95 करोड़ रुपये का चन्दा मिला है। बाकी पार्टियों को मिलने वाला चन्दा भी भाजपा को पूँजीपतियों से मिले चन्दे की तुलना में नगण्य है। भाजपा की मौजूदा ताक़त के पीछे सबसे अहम पहलू मालिकों, ठेकेदारों, बिचौलियों, बिल्डरों, धनी दुकानदारों आदि का यह समर्थन ही है। **जो जिसका खाता है, उसी का हुक्म बजाता है। ज़ाहिर है, भाजपा और ये सभी पार्टियाँ उन्हीं जमातों की सेवा करेंगी, जिनके धनबल पर ये चल रही हैं। हम इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है।**

बिना हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है!

साथियो, देश के मौजूदा हालात चीख-चीखकर बता रहे हैं कि देश की आज़ादी के 75 सालों बाद भी समानता और न्याय पर टिका वह समाज नहीं बना है जिसका सपना शहीदे-आज़म भगतसिंह और उनके साथियों ने देखा था। भगतसिंह ने कहा था – **"कांग्रेस की लड़ाई का अन्त किसी न किसी समझौते या असफ़लता में होगा। इसका परिणाम यह होगा कि गोरे साहब चले जायेंगे और भूरे साहब राज करेंगे। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हों, तो इससे जनता को क्या फर्क पड़ेगा?"** आज आप कांग्रेस की जगह 'सभी धन्नासेठों की पार्टियाँ' लिख दें, तो शहीद भगतसिंह का यह उद्धरण एकदम प्रासंगिक हो जाता है।

आज इन क्रान्तिकारी शहीदों का यह सपना हमारे सामने सवाल के रूप में खड़ा है। उन्होंने जिस लड़ाई को शुरू किया था, उसे अंजाम तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है।

शुरुआत कहाँ से की जाय? यह सबसे अहम सवाल है। शुरुआत करनी होगी हमें अपनी रोज़मर्रा की जिन्दगी से। हमारे बुनियादी अधिकारों से। भगतसिंह ने कहा था जो सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करे, उसे उखाड़ फेंकना जनता का कर्तव्य है। यदि हमें शिक्षा, रोज़गार, चिकित्सा, आवास, सामाजिक-आर्थिक

सुरक्षा, जनवादी अधिकार, सच्चा सेक्युलरिज्म और जनपक्षधर संस्कृति और मूल्य देने में मौजूदा सरकार और व्यवस्था नाकाम है, तो हमें उसे हटाकर एक नयी जनपक्षधर व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें उत्पादन, राज-काज और समाज के पूरे ढाँचे पर उत्पादन करने वाले मेहनतकश लोगों का नियन्त्रण हो और फैसला लेने की ताक़त मेहनतकशों की लोकस्वराज्य पंचायतों के हाथों में हो। **यह दूरगामी लक्ष्य है।** इस दूरगामी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत अपने इन अधिकारों के लिए मौजूदा सरकार और व्यवस्था से संगठित और एकजुट संघर्ष के साथ करनी होगी। इसी संघर्ष के लिए जनता को जगाने के लिए **भगतसिंह जनअधिकार यात्रा** निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण माँगों को उठा रहे हैं, उसके बारे में जनता को जगा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष के वास्ते जनता को गोलबन्द और संगठित कर रहे हैं। यह यात्रा कई चरणों में निकाली जायेगी, जिसके तहत गाँव-गाँव, नगर-नगर यात्रा टोलियाँ जनता के बीच जाएँगी और एक नयी क्रान्ति की अलख जगाएँगी। आपकी भागीदारी इसमें बेहद ज़रूरी है। यह आपकी यात्रा है, आपके अधिकारों के लिए है।

हमारी माँगें

1. रोज़गार को मूलभूत अधिकार के तौर पर संविधान में शामिल किया जाय। **भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी योजना (बसनेगा)** को संसद में पारित करो, जिसके तहत सभी काम करने योग्य नागरिकों को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी हो और ऐसा न कर पाने की सूरत में कम-से-कम रु. 10,000 बेरोज़गारी भत्ता दिया जाय। सभी राज्य सरकारों से माँग है कि वे अपनी-अपनी विधानसभाओं में ऐसे रोज़गार गारण्टी कानून को पारित करें। जो शासक पार्टी इससे इंकार करती है, वह स्पष्ट तौर पर जनविरोधी है।

तात्कालिक तौर पर, **सभी रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती** की जाय, उसके लिए आवश्यक परीक्षाओं का आयोजन किया जाय, सार्वजनिक उपक्रमों के **निजीकरण को रोका जाय** और देश के विकास हेतु शिक्षा, चिकित्सा, अवरचना निर्माण, आवास आदि की सुविधाओं के विस्तार के लिए **नयी रिक्तियाँ निकाली जाएँ** और उन पर भर्तियाँ की जाएँ। **'अग्निवीर' योजना को तत्काल रद्द किया जाय। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाय।**

2. सभी **श्रम कानूनों** को सख़्ती से लागू किया जाय, नये प्रस्तावित लेबर

कोड्स को रद्द किया जाय, **8 घण्टे के कार्यदिवस, साप्ताहिक अवकार, डबल रेट से ओवरटाइम, यूनियन बनाने के अधिकार, सुरक्षा प्रावधानों के अधिकार** को सुनिश्चित किया जाय, **अनौपचारिक क्षेत्र के कल-कारखानों को सरकारी विनियमन में लाया जाय**, **नियमित प्रकृति के कामों पर ठेका प्रथा को समाप्त किया जाय**, और श्रम कानूनों के उल्लंघन को आपराधिक श्रेणी में लाकर दण्डनीय बनाया जाय।

3. महँगाई पर नियन्त्रण के लिए **जमाखोरी, भविष्य व्यापार (फ्यूचर्स ट्रेड) व सट्टेबाज़ी** पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाय जिसके तहत ये दण्डनीय अपराध घोषित किये जाएँ, **बुनियादी वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की व्यवस्था का राष्ट्रीकरण** किया जाय और सरकार उसे पूर्णत: अपने हाथों में ले, खाद्यान्न की कीमतों को बढ़ाने वाले लाभकारी मूल्य की व्यवस्था को समाप्त किया जाय, सरकारी ख़रीद के लिए औसत लाभ सुनिश्चित करने वाली कीमत निर्धारित की जाय और इस ख़रीद की व्यवस्था तक ग़रीब व मँझोले किसानों की पहुँच को सुनिश्चित किया जाय, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** को सार्वभौमिक बनाकर सभी नागरिकों को भोजन मुहैया कराया जाय।

महँगाई को कम करने का एक अहम रास्ता है कि **अप्रत्यक्ष करों को पूर्णत: समाप्त किया जाय और सम्पत्ति के आधार पर प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था को मज़बूत किया जाय।** हम मेहनतकश लोग इस देश में सम्पदा सृजित करने में अपनी मेहनत से पहले ही अपना योगदान दे चुके होते हैं। अप्रत्यक्ष करों द्वारा हमें सरकार लूटती है। यदि अप्रत्यक्ष कर न हों तो पेट्रोल-डीज़ल-रसोई गैस आदि की कीमत तत्काल आधी या एक-तिहाई हो जायेगी और हर आवश्यक वस्तु और सेवा ही सस्ती हो जायेगी। लेकिन मोदी सरकार और इसके पहले की कांग्रेस सरकारें लगातार प्रत्यक्ष करों को घटाती जा रही हैं, जिसका लाभ अमीरों को मिलता है और अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाती जा रही है, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा ग़रीबों को होता है।

4. **शिक्षा को मूलभूत अधिकार के तौर पर संविधान में शामिल किया जाय। जनविरोधी नयी शिक्षा नीति – 2020 को रद्द किया जाय।** सभी नागरिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक समान एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाय और शिक्षा के निजीकरण को समाप्त किया जाय। शिक्षा को

शारीरिक श्रम से जोड़ा जाय, सैन्य प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाय, उसे वैज्ञानिक व तार्किक बनाया जाय और उसे पूर्ण रूप से जनवादी और सेक्युलर स्वरूप दिया जाय।

5. 'सर्वधर्म समभाव' के नकली सेक्युलरिज्म के स्थान पर **सच्चे सेक्युलर राज्य** को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाया जाय जिसके तहत **किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा किसी भी धर्म, समुदाय अथवा आस्था का सार्वजनिक जीवन में किसी भी रूप में उल्लेख करना, उसका इस्तेमाल करना दण्डनीय अपराध हो।** सरकार हर प्रकार के धार्मिक कार्य से अपने आपको पूर्ण रूप से अलग करे, चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखता हो। सभी स्कूलों, कॉलेजों में, सरकारी विभागों आदि में किसी भी धर्म के प्रतीक, चिह्न अथवा प्रार्थना को प्रतिबन्धित किया जाय।

6. न सिर्फ अस्पृश्यता (छुआछूत) को बल्कि **किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में जातिगत भेदभाव को दण्डनीय अपराध घोषित करने हेतु संविधान में संशोधन किया जाय।** जातिगत आधार पर संगठन बनाने, संस्थाएँ बनाने, वैवाहिक विज्ञापन आदि पर पूर्ण रोक हो।

7. तमाम चुनावी दलों व सरकार द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाय और इसके लिए जनता द्वारा चुनी गयी जनकमेटियों की देखरेख में इनके **पब्लिक ऑडिट व जाँच** की व्यवस्था की जाय। तमाम जाँच व निगरानी संस्थाओं को न सिर्फ सरकार के नियन्त्रण से बाहर किया जाय, बल्कि उनकी जवाबदेही इन जनकमेटियों के प्रति सुनिश्चित की जाय।

8. सभी नागरिकों को **आवास का मूलभूत अधिकार** दिया जाय। इसके लिए विशेष कानून बनाया जाय और राजकीय आवास की सार्वभौमिक व्यवस्था की जाय, जहाँ मकान को बेचने-ख़रीदने, सम्पत्ति की ख़रीद-फ़रोख़्त में सट्टेबाज़ी आदि पर पूर्ण रोक हो।

9. स्त्रियों व पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन हेतु सख़्त कानून बनाया जाय। स्त्रियों से हर रूप में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक सख़्त कानून बनाये जाएँ, हालाँकि सिर्फ कानूनों से ही लैंगिक असमानता समाप्त नहीं हो सकती, जब तक कि समूचा सामाजिक-आर्थिक ढाँचा ही न बदला जाय।

10. ग़रीब व मँझोले किसानों (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) के लिए **बीज,**

खाद, बिजली आदि पर सब्सिडी की समुचित व्यवस्था के लिए अमीर वर्गों पर विशेष कर लगाये जाएँ। उनके लिए **सिंचाई की व्यवस्था के व्यापक नेटवर्क** के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में ले और उनके लिए आसान शर्तों और कम ब्याज़ दर वाले **संस्थागत ऋण** की व्यवस्था की जाय ताकि वे धनी फार्मरों, आढ़तियों, व्यापारियों, सूदखोरों आदि से ऊँची ब्याज़ दर पर कर्ज़ लेने की मजबूरी से आज़ाद हो सकें। तात्कालिक तौर पर, **मनरेगा योजना** के तहत आबण्टन को बढ़ाया जाय, उसके तहत पूरे साल के रोज़गार का अधिकार दिया जाय और उसके तहत कम से कम तय न्यूनतम मज़दूरी जितनी राशि का भुगतान किया जाय।

11. धार्मिक व जातिगत वैमनस्य भड़काने, हिंसा व 'मॉब लिंचिंग' आदि में संलग्न हर प्रकार के संगठन, दल आदि पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया जाय और उनके नेताओं-कार्यकर्ताओं पर तत्काल कार्रवाई की जाय।

आइये, एक नयी शुरुआत करें...

साथियो, हमारे दिमाग में हुक्मरानों ने यह बात बिठा दी है कि उपरोक्त माँगे तो पूरी हो ही नहीं सकतीं या ये असम्भव हैं। हम भी बार-बार दुहराये जाने से यह मान बैठते हैं। **यदि सरकार उपरोक्त जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकती है, तो वह आख़िर है किसलिए? केवल अमीरों को ग़रीबों की लूट की खुली छूट और व्यवस्था देने के लिए ताकि अमीर और अमीर बन सकें और ग़रीब और ग़रीब होता जाय?**

वास्तव में, उपरोक्त में से कई अधिकार दुनिया में विभिन्न देशों में जनता को हासिल हैं या हासिल रहे हैं। इससे इतना तय है कि यह सम्भव है। इसलिए सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये सरकार के काम नहीं हैं, या ये सम्भव नहीं है। येबिल्कुल सरकार के ही काम हैं और बिल्कुल सम्भव है।

अगर कोई सरकार इन बुनियादी जिम्मेदारियों से ही मुँह मोड़ती है, आबादी आदि का तर्क देकर तमाम समस्याओं का ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ती है, तो उसे सरकार बने रहने का कोई हक़ नहीं है। **आबादी अपने आप में कोई समस्या नहीं होती। यदि ऐसा होता तो हॉलैण्ड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों को भारत से ग़रीब होना चाहिए था क्योंकि इन देशों का जनसंख्या**

घनत्व भारत से ज़्यादा है, यानी हर वर्ग किलोमीटर में इन देशों में भारत के मुकाबले ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इन देशों में शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन, पोषण आदि सभी मसलों में भारत से कहीं अच्छी स्थिति है। साथ ही, इन देशों के पास भारत जैसी विराट और वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भी नहीं है। इन देशों में भी पूँजीवादी शोषण, लूट और असमानता है और हमारे लिए ये कोई आदर्श नहीं हैं। **लेकिन इतना तो साफ़ है कि अगर देश की समस्याओं के लिए अपने आप में आबादी जिम्मेदार होती तो फिर इन देशों को भारत से कम विकसित और पीछे होना चाहिए था। केवल इतने तथ्य से आबादी का तर्क ख़ारिज किया जा सकता है।** आबादी का तर्क मौजूदा व्यवस्था अपनी नाकामी के लिए आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए बनाती है, ताकि इस जनविरोधी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करने के बजाय हम अपने आपको और एक-दूसरे को ही कोसते रहें।

इसलिए उपरोक्त माँगों को समझें, उन माँगों पर एकजुट हों, संगठित हों और उनके लिए संघर्ष करें। अन्य सभी बातों, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के बँटवारों को भूलकर साथ आएँ। भगतसिंह जनअधिकार यात्रा इसी मक़सद से निकाली जा रही है।

हम आप सभी से इस यात्रा में शामिल होने की हार्दिक अपील करते हैं। शहीदे आज़म भगतसिंह के सपनों के समाज के निर्माण की दिशा में यह एक शुरूआती कदम है। हमारे सामने लम्बी कठिन यात्रा है। लेकिन लम्बी से लम्बी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। इस पहले कदम को उठाने में हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ और इस यात्रा में शामिल हों। आपके गाँव या शहर में यात्रा की तिथियों व कार्यक्रम की जानकारी के लिए इस पुस्तिका के पीछे दिये फोन नम्बरों या ईमेल पतों पर सम्पर्क करें।

लड़ेंगे, जीतेंगे!
शिक्षा और रोज़गार-हमारा जन्मसिद्ध अधिकार!
अन्धकार का युग बीतेगा-जो लड़ेगा वो जीतेगा!
इंक़लाब ज़िन्दाबाद!